पटना में

6 अक्तूबर, 90—जसस की बिहार-रैली

7-8 अक्तूबर, 90—जसस का पहला राष्ट्रीय सम्मेलन

सही संकल्प के सहभागी बनें

साथी,

आगामी 7-8 अक्तूबर, 90 को पटना में **जनांदोलन समन्वय समिति (जसस)** का पहला राष्ट्रीय सम्मेलन होने जा रहा है। इसी मौके पर 6 अक्तूबर को जसस की बिहार-स्तरीय रैली भी होने वाली है। सम्मेलन के जरिये एक वैचारिक मसविदा घोषित होने वाला है और रैली के मारफत बिहार के विकास का माँगपत्र सरकार के सामने पेश किया जाने वाला है।

आपको जानकारी होगी ही कि **जसस** देश भर के शांतिमय, लोकतांत्रिक व परिवर्तनवादी शक्तियों के समन्वय की पिछले तीन-चार वर्षों से चल रही कोशिश का निष्कर्ष है। **छात्र युवा संघर्ष वाहिनी, समता संगठन, उतजास, उत्तराखंड जन संघर्ष वाहिनी, कर्नाटक दलित संघर्ष समिति, युवक क्रान्ति दल** और **जनमुक्ति संघर्ष वाहिनी (जसवा)** जैसे संगठन अभी **जसस** के हिस्सेदार हैं। **जसस** की यह सोच है कि लगातार विभिन्न संगठनों और आंदोलनों को उनकी पूरी स्वायत्तता के साथ इस समन्वय में शामिल किया जाता रहेगा।

जसस की यह पहल आज देश के सामने खड़े एक भयावह संकट को मद्देनजर रखते हुए की गयी है। विनाश हमारे सामने खड़ा है। अगर वक्त रहते इस संकट का समाधान न तलाशा जा सका, पूरा देश बरबादी के गर्त में चला जायेगा। देश का अवाम आज अपमानित, उत्पीड़ित और शोषित तो है ही, भविष्य तो उसके अस्तित्व पर ही सवाल खड़ा करने वाला है। संकट के सैकड़ों रूप हमारे सामने मंडरा रहे हैं। पर सारी परम्परागत राजनीतिक ताकतें अपनी राह चलने में मशगूल हैं। इनमें समाधान की संकल्प-शक्ति नहीं है। कई समस्याओं पर तो उनके पास सही नजरिया भी नहीं है। उनकी परम्परागत दृष्टि कई समस्याओं को भयावह बनाते जाने का ही काम करती है। वामपंथी पहचान की ताकतें भी इन मामलों में अपना अलग चरित्र पेश करती नहीं दिखती।

राष्ट्रीय मोर्चा सरकार से जनता में उम्मीदें जगी थीं। पर आज सारी उम्मीदें ढह रही हैं। इस सरकार ने जितने ऊँचे वायदे किए थे, उनमें किसी के भी प्रति इसकी प्रतिबद्धता नहीं है। एक ओर यह सरकार काम के अधिकार को मूलभूत अधिकारों में शामिल कर रही है। दूसरी ओर उत्पादन के हर क्षेत्र में निजी पूँजीपतियों को बड़े और पूँजीप्रधान उद्योगों को खड़ा करने हेतु आमंत्रित कर रही है। इस स्थिति में तो

काम का अधिकार महज संविधान में दर्ज चंद लकीरों की हैसियत में रह जायगा। यह सरकार संचार माध्यमों की स्वायतता की बात करती रही है। पर सच्ची स्वायतता संदिग्ध ही है, क्योंकि आज भी इन माध्यमों पर शासकीय नियंत्रण और पूर्वाग्रह व्यक्त हो रहे हैं। चुनाव पद्धति में सुधार की कोई पहल नहीं है। कश्मीर, पंजाब असम, झारखंड जैसे मसलों पर उसका रवैया पिछली सरकार से तनिक भी अलग नहीं है। कश्मीर की हालत को और बदतर बनाने का काम ही मौजूदा सरकार ने किया है। हाल के दिनों में सरकार के अन्दर जो फेरबदल हुआ है, वह कोई नीतियों के लड़ाई का नतीजा नहीं, बल्कि सत्ता में अपनी ताकत बढ़ाने की टकराहट थी। इस टकराहट से इस सरकार से बची-खुची उम्मीदें भी खत्म हो जाती हैं।

यानी देश की राजनीति के सामने अभी या तो कांग्रेसी और गैरकांग्रेसी शासन के भंवर में फंसे रहने की मजबूरी है या एक त्रासद राजनीतिक शून्यता को झेलने की बाध्यता है। पक्ष-विपक्ष की राजनीतिक शक्तियां अवाम की दिक्कतों से बेखबर हैं। वेतन, भत्ता, फाइवस्टार होटल, हवाई उड़ान और विदेशी दौरों की सुविधा-वृद्धि के मसले पर सबों में सर्वसम्मति है। सभी दल समस्याओं के जिक्र की औपचारिकता भर पूरी करते हैं। योजनाओं व कायदों के निर्माण के वक्त सारी ताकतें जनता का हित दरकिनार कर देती हैं।

निष्कर्षतः आज की राजनीति की मुख्यधारा में सही राजनीतिक ताकत की अनुपस्थिति है। एक घातक राजनीतिक शून्यता संभावित है। सही व जनपक्षधर राजनीतिक शक्ति के विकल्प का अभाव आज का मुख्य राजनीतिक संकट है। आज देश, वक्त व हालात की तीसरी ताकत का तकाजा है। इस विकल्पहीनता व शून्यता को समाप्त करने की शक्ति आज के समाज में ही अन्तर्निहित है। देश के विभिन्न अंचलों में चल रहे जनांदोलन अच्छे कल की उम्मीद के आशास्तंभ हैं। इन्हें पहचानने, आपस में जोड़ने और फैलाने की जरूरत है। जसस इसी समझ से बनी है और यही जिम्मेवारी निभाने के संकल्प से लैस है।

आप मौजूदा दौर के संकट को गंभीरता से समझते हैं। इस संकट के समाधान की दृढ़ व इमानदार पहल की अनिवार्यता भी आप समझते हैं। अतः आप ऐसी एक संवेदनशील पहल जसस के इन कार्यक्रमों को कामयाब बनाने हेतु अपना भरपूर समर्थन व सहयोग दें।

निवेदक

जनांदोलन समन्वय समिति
छात्र-युवा संघर्ष वाहिनी कार्यालय
12-राजेन्द्रनगर, पटना-800016

28 अगस्त, 90

मुद्रक :— लोकवाणी प्रिंटिंग प्रेस, नयाटोला, पटना-4